

द्वपिक्षीय नविश संधियाँ

प्रलिमिंस के लयि:

[द्वपिक्षीय नविश संधियाँ \(BITs\)](#), [केंद्रीय बजट 2024-25](#), [प्रत्यक्ष वदिशी नविश \(FDI\)](#) ।

मेन्स के लयि:

द्वपिक्षीय नविश संधियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के लयि FDI का महत्त्व ।

[स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

अंतरमि [केंद्रीय बजट 2024-25](#) प्रस्तुत करते हुए, भारतीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत [प्रत्यक्ष वदिशी नविश \(Foreign direct investment- FDI\)](#) के प्रवाह को बढ़ावा देने के लयि अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ [द्वपिक्षीय नविश संधियाँ \(Bilateral Investment Treaty- BITs\)](#) पर बातचीत करेगा ।

- वशिष रूप से वर्ष 2016 में [BIT मॉडल](#) को अपनाने के बाद से भारत की द्वपिक्षीय संधियाँ समाप्त हो गई हैं ।

द्वपिक्षीय नविश संधियाँ (BITs) क्या हैं?

- परचिय:**
 - BITs दो देशों के बीच एक-दूसरे के क्षेत्रों में वदिशी नजि नविश को बढ़ावा देने एवं उसकी सुरक्षा करने के लयि पारस्परिक समझौते हैं ।
 - 90 के दशक के मध्य से भारत सरकार ने वदिशी नविशकों एवं नविशों को अनुकूल परिस्थितियों के साथ संधि-आधारित सुरक्षा प्रदान करने के लयि BIT की शुरुआत की ।
- न्यूनतम गारंटी:**
 - BIT वदिशी नविश व्यवहार के संबंध में दोनों देशों के बीच न्यूनतम गारंटी स्थापित करते हैं, जैसे,
 - राष्ट्रीय व्यवहार (वदिशी नविशकों के साथ घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार करना)
 - नषिक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार (अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार)
 - जबती से सुरक्षा (प्रत्येक देश की अपने क्षेत्र में वदिशी नविश प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करना) ।
- BITs के अंतरगत मध्यस्थता:**
 - BITs सामान्य रूप से नविशकों एवं नविश करने वाले देश के बीच वविादों को नपिटाने के लयि एक तंत्र प्रदान करते हैं ।
 - ऐसे वविादों को नपिटाने के लयि सर्वाधिक चुना जाने वाला तरीका मध्यस्थता है, जहाँ पक्ष न्यायालय में जाने के स्थान पर अपने वविाद का नरिणय किसी तटस्थ व्यक्ती (मध्यस्थ) द्वारा कराये जाने पर सहमती व्यक्त करते हैं ।
- इतहिस:**
 - भारत द्वारा पहला BITs, वर्ष 1994 में UK के साथ हस्ताक्षरित किया गया था ।
 - वर्ष 2010 में भारत के खिलाफ दायर पहली नविशक संधि दावे के नपिटान के साथ BITs संधिने ध्यान आकर्षित किया ।
 - वर्ष 2011 में भारत को ऑस्ट्रेलिया-भारत BITs (व्हाइट इंडस्ट्रीज़ बनाम रपिब्लिक ऑफ इंडिया) से उत्पन्न वविाद में अपना पहला प्रतिकूल भुगतान करना पड़ा, जहाँ भारत सरकार को इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 4.1 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था ।
 - वर्ष 2015 तक भारत को 17 ज्ञात BITs दावों का सामना करना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश तेल और गैस कंपनी **केयर्न एनर्जी Pic** का दावा

भी शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला।

- सरकारी खजाने पर बढ़ रहे बोझ को देखते हुए, सरकार वर्ष 1993, **BIT मॉडल** पर फरि से वचिार करने के लयि वविश हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष **2016 मॉडल BIT को अपनाया** गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने संशोधति पाठ के आधार पर शर्तों पर पुनर्वचिार करने के अनुरोध के साथ वर्ष **2015 तक नविषादति 74 संधियों में से 68 को समाप्त** कर दयिा।
 - वर्ष 2016, BIT मॉडल को अपनाने को वदिशी नविश को प्रोत्साहति करने के लयि एक सूक्ष्म तथा कैलबिरेटेड (अंशांकति) दृष्टिकोण के स्थान पर एक तत्काल संरक्षणवादी उपाय के रूप में देखा गया था।

वर्ष 2016 मॉडल BIT के साथ क्या चुनौतियाँ रही हैं?

■ नविश की संरक्षित परिभाषा:

- BIT मॉडल द्वारा BIT सुरक्षा के लयि अरहता प्राप्त करने के लयि आवश्यक नविश की परिभाषा को सीमति कर दयिा। BIT मॉडल इंगति करता है कि **भारत नविश के लयि एक संकीर्ण 'उद्यम-आधारति' परिभाषा को प्रस्तावति** करता है, जिसके तहत संधि के तहत केवल प्रत्यक्ष नविश को संरक्षति कयिा जाता है।
- इसमें एक नकारात्मक सूची भी शामिल है, जो नविश की परिभाषा से पोर्टफोलयिो नविश, ऋण-प्रतभूतियों में ब्याज, अमूर्त अधिकार इत्यादि को अलग करती है।
- इस प्रकार नई परिभाषा वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के आधुनकि युग में वदिशी नविश के बढ़ते दायरे को ध्यान में नहीं रखती है।

■ घरेलू उपचार खण्ड की समाप्ति:

- BIT मॉडल में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने से **पूर्व घरेलू उपचार की समाप्ति को अनविर्य** करने वाला एक खंड शामिल है।
- वर्ष 2016, BIT मॉडल में प्रावधान कयिा गया है कि एक नविशक को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने से पूर्व स्थानीय व्यवहार का उपयोग करना होगा।
- यह नश्चति रूप से वदिशी नविशकों में वशिवास बढ़ाने के लयि बहुत कम है।

■ FDI पर प्रभाव:

- अन्य देशों के साथ शर्तों पर पुनः बातचीत करने में आने वाली कठिनाइयों ने भी FDI को आकर्षति करने में चुनौतियों में योगदान दयिा है।
- अप्रैल-सतिंबर 2023 में भारत में FDI इक्वटि प्रवाह 24% घटकर 20.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
 - कुल FDI- जिसमें इक्वटि प्रवाह, पुनर्नविश आय तथा अन्य पूंजी शामिल है, अप्रैल-जून 2022 में 38.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले समीक्षाधीन अवधि के दौरान 15.5% घटकर 32.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

■ मेज़बान राज्य को व्यापक वविकाधीन शक्तियाँ:

- संधि में नविश के उचित व्यवहार को सुनिश्चति करने वाला एक खंड शामिल था, जो दोनों पक्षों को ऐसे उपायों को लागू करने से **रोकता** है जो स्पष्ट रूप से अपमानजनक हैं या उचित प्रक्रयिा का उल्लंघन करते हैं।
- हालाँकि, "उचित प्रक्रयिा" के उल्लंघन के मूल्यांकन का पैमाना क्या है, यह परिभाषति नहीं कयिा गया है।
- इसके अतिरिक्त BIT मॉडल में कहा गया है कि यदि मेज़बान राज्य यह नरिणय लेता है कि BIT के तहत कथति उल्लंघन किसी भी समय कराधान का वषिय है, तो मेज़बान राज्य का नरिणय गैर-न्यायसंगत होगा और साथ ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा से छूट दी जाएगी।
 - मॉडल BIT मानता है कि एक वदिशी नविशक को घरेलू न्यायकि व्याख्याओं एवं तंत्रों पर पूर्ण वशिवास होगा।
 - यह संभावति रूप से मेज़बान राज्य को किसी भी वविाद को न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से एकतरफा बाहर करने का व्यापक अधिकार दे सकता है, केवल इस आधार पर कि प्रश्न में आचरण कराधान से संबंधति है।

आगे की राह

- वदिशी नविशकों और घरेलू अर्थव्यवस्था दोनों के हतियों को संतुलति करते हुए यह सुनिश्चति करने के लयि **कि यक्षैश्वकि सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखति** हो, भारत अपनी BIT व्यवस्था पर फरि से वचिार कर सकता है। इसमें नविषिा एवं न्यायसंगत व्यवहार, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा एवं मज़बूत वविाद समाधान तंत्र के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
- वविादों के समय पर नपिटान की सुवधि के साथ **नविशक राज्य वविादों में प्रभावी प्रतनिधित्व सुनिश्चति करने के लयि वर्ष 2021 में वदिशी मामलों पर संसदीय स्थायी समतिि द्वारा की गई सफिराशियों**, जैसे मध्यस्थता पूर्व परामर्श एवं बातचीत को बढ़ावा देने के साथ लागू करना।
- भारत को नविशक राज्य वविादों को प्रभावी ढंग से संभालने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लयि नविश मध्यस्थता के क्षेत्र में स्थानीय वशिषज्जता वकिसति करने में नविश करना चाहयि। इसमें प्रशकिषण पेशेवरों एवं कानूनी वशिषज्जों को शामिल कयिा जा सकता है, साथ ही नविश मध्यस्थता के लयि वशिष संस्थान भी बनाए जा सकते हैं।
- भारत को BIT के लयि एक प्रगतशील दृष्टिकोण अपनाना चाहयि जो नयिमक संप्रभुता की अनविर्यता के साथ नविशक सुरक्षा की आवश्यकता को संतुलति करता है। इसमें नविशकों के अधिकारों के साथ-साथ सतत् वकिस, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजकि कल्याण को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को भी शामिल कयिा जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: नमिनलखति पर वचिार कीजयि: (2021)

1. वदिशी मुद्रा परिवर्तनीय

2. कुछ शर्तों के साथ वदेशी संस्थागत नविश
3. वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें
4. अनवासी बाहरी जमा

उपर्युक्त में से किसको परत्यक्ष वदेशी नविश में शामिल किया जा सकता है?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 4
- (d) केवल 1 और 4

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bilateral-investment-treaties-1>

